

के आचार्य तथा निदेशक के पदों के लिये कोई विशेष योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ;

(स) क्या इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास ये योग्यताएँ हैं ;
मोर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैज्ञानिक ग्रनेवरण और सांस्कृतिक कार्यालयों (भी हथायू कबीर) : भाग (क) से (ग), १६४८ में जब प्रिसिपल की भरती की गई थी तो कुछ आवश्यक अनुभव और योग्यतायें निर्धारित की गई थीं। वर्तमान अधिकारी के पास वे सब योग्यतायें प्राप्त अनुभव हैं।

डायरेक्टर के पद के लिये सास तौर पर विशेष योग्यताये निर्धारित नहीं की गई। वर्तमान अधिकारी प्रसिद्ध जिआलिजिस्ट हैं और अपने क्षेत्र में खबर अनुभवी हैं।

Monuments in Punjab

2898. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Scientific Research and Cultural Affairs be pleased to state the amount sanctioned for the protection and improvement of monuments in Punjab

by the Central Government during
1958-59?

The Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Shri Humayun Kabir): Final allocation of the amount to be spent during 1958-59 on the maintenance of the monuments of national importance in the various Circles of the Union Department of Archaeology has not yet been made.

Census of Wealth

2899. { Shri R. S. Arumugam:
Shri Elayaperumal:

Will the Minister of Finance be pleased to state the number of families in the country whose properties excluding agricultural properties are worth between Rs. 2 lakhs to 10 lakhs, 10 lakhs to 25 lakhs, 25 lakhs to 50 lakhs, 50 lakhs to 1 crore and above one crore category-wise and State-wise?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): A rough estimate of number of families (Individuals and Hindu Undivided Families) whose wealth excluding agricultural properties, fall under the various categories is given below according to the charges of the Commissioners of Wealth-tax. As some of the Commissioners hold jurisdiction over more than one State, separate figures for some of the States are not readily available:—

Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs	Rs. 10 lakhs to 25 lakhs	Rs. 25 lakhs to 50 lakhs	Rs. 50 lakhs to 1 crore	Above 1 crore
	Ind. HUFs	Ind. HUFs	Ind. HUFs	Ind. HUFs	Ind. HUFs
Bombay . . .	8094	614	481	41	..
West Bengal . . .	3467	279	163	34	..
Punjab and Jammu & Kashmir . . .	551	154	16	8	..
Delhi and Rajasthan . . .	1206	217	51	6	..
Uttar Pradesh . . .	523	211	27	3	..
Bihar & Orissa . . .	375	242	21	9	..
Assam . . .	232	95	5	1	..

Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs	Rs. 10 lakhs to 25 lakhs	Rs. 25 lakhs to 50 lakhs	Rs. 50 lakhs to 1 crore	Above 1 crore
Madhya Pradesh .	Ind. HUFs 481	Ind. HUFs 159	Ind. HUFs 29	Ind. HUFs 14	Ind. HUFs 3
Andhra Pradesh .	772	233	47	8	9
Mysore .	729	193	19	11	1
Madras .	1160	280	35	6	4
Kerala .	454	96	27	5	3
TOTAL .	18044	2773	921	146	169
					29
					40
					10
					22
					..

निवृति वेतन के मामले

२६००. { श्री लालदीवाला :
 श्री क० भे० मालवीय :
 श्री दलचरील सिंह :
 श्री न० अ० देव :

क्या बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृति के पश्चात् उनका निवृति वेतन के मामले निवाटने के लिये कितनी अवधि नियन्त की गई है ; और

(ख) निवृति वेतन के कितने मामले में महीने, एक साल, दो साल अथवा पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

बिल मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) इसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है ; परं पेंशन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निवाटने वाले सभी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है कि जिस अफसर को जिस दिन से पेंशन मिलनी हो उसे वह उसी दिन से मिलने लगे। यदि किसी व्यास मामले में देर लगे बिना काम न हो तो अन्त में जितनी पेंशन निश्चित होने का अनुमान हो उसके हिसाब से अफसर को कुछ रकम दी जाने लगती है ताकि उसे कट्ट न हो।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह प्राप्त नहीं है। सारे देश में बैंडीय सरकार वे जितने दफ्तर हैं, उनसे यह सूचना प्राप्त करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा।

निवृति वेतन

२६०१. { श्री लालदीवाला :
 श्री क० भे० मालवीय :

क्या विल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) बैंडीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितना निवृति वेतन मिल मिलता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृति वेतन को न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि निवृति वेतन की अधिकतम सीमा नहीं निश्चित की गई है : और

(ग) यह सीमा किन मिदानों पर अधारित है ?

बिल मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बैंडीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितनी पेंशन दी जाये, इसके बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह निर्धारित कर दिया गया है कि पेंशन पाने के लिये पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करने वाली अधिक से अधिक कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिये और विहित नियम के अनुसार अधिक से अधिक कितनी पेंशन दी जानी चाहिये।